13. Shri S. K. Vaishampayen

14. Prof. A. R. Wadia

15. Shri M. C. Chagla (the mover);

and 30 Members from the Lok Sabha;

that in order to constitute a meeting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Select Committees shall apply with such variations and modifications as the Chairman may make;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session; and

that this House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of Members to be appointed by the Lok Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

THE REPEALING AND AMENDING BILL, 1964

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI JAGANATH RAO): Madam, on behalf of Mr. A. K. Sen, I beg to move:

"That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments be taken into consideration."

This Bill is a purely formal measure and the reasons for sponsoring the Bill are set out in the Statement of Objects and Reasons appended to the Bill. The enactments that are sought to be repealed are mentioned in Schedule I annexed to the Bill. These enactments have ceased to be in operation or they have become unnecessary. The enactments which are sought to be amended are appended in the Second Schedule to the Bill.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) in the Chair].

These amendments are purely formal in nature and are aimed at correcting technical errors or defects. The notes on clauses appended to the Bill mentions the reasons why certain enactments are sought to be repealed and the reasons why certain amendments are sought to be introduced to the Acts appended in Schedule II. This is one of the formal routine measures introduced periodically. The last Repealing and Amending Act was passed in 1960 and this Bill seeks to repeal certain enactments enumerated in Schedule I and amend certain enactments which are enumerated in Schedule II, and the whole idea is to bring the Statute Book up-to-date and remove from the Statute Book enactments which have ceased to operate and whose continuance is considered unnecessary. This opportunity is availed of to introduce certain amendments which are purely of a formal or technical nature. As I submitted, this measure is of a very non-controversial and formal nature and I commend this motion for the acceptance of the House. I move.

The question was proposed.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, यह बिल जो प्रस्तुत किया गया है इसमें कुछ कानूनों को रिपील किया गया है और कुछ में संशोधन किया गया है। इन संशोधन किए गए कानूनों की यादी में अभी हाल ही में १९६१ में, १९६२ में और १९६३ में जो कानून बने वे भी हैं और उनमें भी संशोधन चाहा है। वे संशोधन कोई ऐसे बड़े नहीं है कि कोई विशेष आपत्ति हो, शाब्दिक गल्ती होने की वजह से उनको ठीक करने की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से ठीक करने के लिए वे लाए गए है। लेकिन मेरा एक नम्र निवेदन है कि यह कानून का प्रश्न इतने महत्व का है कि यदि इसमें हम थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो उसका सारे देश पर बड़ा भारी असर पड़ता है।

[श्री बिमलकुमार मन्नालालजा चौरड़िया]

एक शब्द को भी गलत रखने से, "बाई" की जगह "टू" या "टू" की जगह "बाई" रखने से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है और उन्हीं फर्कों को ध्यान में रख कर हमारे मंत्री जी यह छोटे छोटे अमेंडमेंट लाए हैं कि "अंडर दिस एक्ट" की जगह "अंदर दिस सेक्शन" या "अंडर दिस सेक्शन" की जगह "इन दिस सेक्शन" या "इन दिस सब-सेक्शन" की की जगह "इन दिस सेक्शन" वगैरह, वगैरह ऐसे छोटे -छोटे संशोधन लाए हैं। तो मैं एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब हम इस काम के लिये विशेष अधिकारी रखते हैं और जिनकी जिम्मेदारी यह है कि बिल्कुल ठीक तरह से कानून बने, कानून की धाराएं ठीक तरह से रखी जायें, उनको ठीक तरह से ये टेक्नीकल बातें करनी हैं। आप और हम तो यहां पर पालिसी बनाने के लिए बैठे हैं, और पालिसी के आधार पर उनके कार्यक्रम होते हैं। लेकिन यह हमारा भी कर्त्तव्य है कि हम भी उन बारीकियों को देखें क्योंकि तुलनात्मक रूप से उन पर जो कर्त्तव्य भार है उसकी अपेक्षा हम पर, हमारी पालिसी के ऊपर ज्यादा है। ऐसी स्थिति में मैं प्रार्थना करूंगा कि उन कारणों को खोजा जाये जिससे कि भविष्य में इस तरह की बातें न हों कि कानूनों में भूल रह जाय।

दूसरे, हमारे यहां पर कानून ऐसे बने हुए हैं जो बहुत अच्छे उद्देश्यों को ले कर बने हुए हैं मगर वे कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाते। उनको अगर हम इसलिये उपयोग में लाऐं कि किसी से हमारा द्वेष है तो उनका लाभ उठाएं तो यह न्यायसंगत नही प्रतीत होता है। उदाहरण के लिये, आप हम और सब लोग चाहते हैं कि छोटे बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिये, बाल विवाह बन्द करने के लिये हमने कानून बनाया है लेकिन इसके बावजूद भी कि आप हम और हमारे संसद सदस्य चाहते हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिये फिर भी छोटी उम्र के बच्चों की शादी होती ही रहती है। विवाह के समय लड़का और लड़की को जो फेरे करने पड़ते हैं वह उनके माता पिता खुद कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को धोका देते हैं जो इन कानूनों को आलमारी की शोभा बढ़ाने के लिये रखते हैं और कुछ लोगों को मौका देते हैं कि वे उनका अनुचित लाभ उठाऐं। जैसे किसी की रिश्तेदारी में आपस में झगड़ा हो तो वह कानून का नाजायज लाभ उठाना चाहेंगे जो कानून की दृष्टि से जायज है और इस प्रकार कानून के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये कानून के जाल में फंसता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि हम एक दफा उन सारे कानूनों को देखें और अगर किसी कानून के ऊपर ठीक तरह से अमल हो नहीं पा रहा है या हम समझें कि उस कानून पर अमल करने के लिये हम सक्षम नही है या उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको वापस ले लें। या तो हम इसके लिये सख्ती से कदम उठाएं कि जिससे छोटी उम्र के बच्चों का विवाह न हो लेकिन यह हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन कानून हमने बना रखा है कि उसके अनुसार छोटी अवस्था के बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिये फिर भी ऐसे विवाह हो रहे हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं।

इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे मंत्री महोदय सारे कानूनों के जंगल की छानबीन करें क्योंकि कानून इतने ज्यादा हो गये हैं कि खुद कानून बनाने वालों को भी मालूम नहीं कब कहां क्या अमेंडमेंट हो गया। जब दो वकील मुकदमा लड़ते समय आमने सामने होते हैं तो इधर उधर से अमेंडमेंट लाते हैं कि फलां अमेंडमेंट हुआ था और फिर आपस में टकराहट होती है। आज के समाज में ज्यों ज्यों अव्यवस्था बढ़ती जाती है त्यो त्यों उस अव्यवस्था को सुधारने के लिये हमें कानून बनाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में सारे कानूनों का अध्ययन करके देखना चाहिये कि कौन से कार्य रूप में परिणत हो रहे हैं,

कहां नहीं हो रहे हैं, कौन से सेक्शन्स हैं जिनको डिलीट कर देना चाहिये या रिपील कर देना चाहिये ।

अन्त में मैं प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रख कर कार्यवाही की जाय तो अच्छा होगा ।

SHRI JAGANATH RAO: Madam, I am very thankful to Mr. Chordia for making some suggestions. First he referred to the carelessness in the drafting of Bills. I may assure him and the hon. House that every care is taken in drafting a legislative measure. But, in spite of all the care that is taken, some defects do creep in and therefore we are anxious to see that such defects do not continue and these defects are removed at the earliest possible time.

Regarding the point raised by him that the Acts which are passed should be fully implemented—as an instance he quoted the Child Marriage Restraint Act—I fully agree with him that all the enactments passed by Parliament should be fully implemented, that there should be no gap between the statute law and the living law. But the amendment sought by this Bill is not repeal of such enactments which are useful and salutary, but enactments which have been rendered unnecessary—some of them have spent out; their life is out. And I can again assure my friend that when a legislative measure is brought forward, by this Ministry or any other Ministry of the Government of India, every care is taken to see that proper attention is devoted and defects, either technical or formal, do not creep in. But in spite of all the care that is taken, here and there there may be some lapses but I assure him that proper attention is being paid and will be paid in future also. Thank you.

THE VICE- CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE): The question is:

"That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE): We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5, the First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGANATH RAO: Madam, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE INDIAN TRADE UNIONS (AMENDMENT) BILL, 1964

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI D. SANJIVAYYA) Madam, I move:

"That the Bill further to amend the Indian Trade Unions Act, 1926, be taken into consideration."

This is a very small Bill and I do not propose to take much time of the House. The Indian Trade Unions Act is a Union Act and it provides for the registration of trade unions in India and to a great extent it defines the responsibilities and rights of trade unions in general. Under section 4 of the Act, any seven workers can form themselves into a union and ask for registration under this Act. The provisions of this Act, however, do not bar any individual who is convicted in any criminal case involving moral turpitude. Now one of the State Governments raised this question because they found it very difficult and embarrassing too that such persons, in their capacity as office-bearers of trade unions began to re-